[2008] 2 एस.सी.आर. 598

बी.के. श्री हर्ष (डी) वि.प्र. द्वारा और अन्य

बनाम

मैसर्स भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

(2004 की सिविल अपील संख्या 6329-6330)

फ़रवरी 8, 2008

(डॉ. अरिजीत पसायत और पी. सदाशिवम, जे.जे.)

विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, *1963;* धारा *16* एवं *20:*

कुछ संपत्तियों की बिक्री के अनुबंध के विनिर्दिष्ट पालन के लिए वाद - विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया कि क्रेता के पास वाद संपत्ति का प्रतिकूल कब्जा था, वह अनुबंध के अपने हिस्से को पूरा करने के लिए तैयार था और प्रतिफल राशि के बड़े हिस्से का भुगतान किया था- सि.प्र.सं. *1908* के आ.*41* नि.*1* में अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय ने अपील खारिज कर दी-

अपील पर, माना गया*:* यद्यपि वाद विनिर्दिष्ट पालन के लिए था, लेकिन विचारण न्यायालय ने प्रतिकूल कब्जे का निष्कर्ष दर्ज किया-

इस प्रकार, विचारणीय बिंदु शामिल हैं-जब विचारणीय बिंदु शामिल हों, तो अपील का संक्षिप्तः खारिज/निपटारा नहीं किया जाना चाहिए-

उच्च न्यायालय द्वारा उठे विवाद्यकों का गंभीरता से विश्लेषण नहीं किया गया- इसलिए, मामला नए सिरे से विचार के लिए उच्च न्यायालय को भेजा गया-

सिविल प्रक्रिया संहिता,*1908*- आ.*41* नि.*1*-अपील-संक्षिप्त निपटान-विचारणीय विवाद्यक

प्रत्यर्थी-कंपनी ने कुछ संपत्तियों के संबंध में अनुबंध के विनिर्दिष्ट पालन के लिए दो वाद दायर की, जिन्हें कथित तौर पर समझौतों के तहत अपीलकर्ताओं द्वारा बेचने पर सहमति व्यक्त की गई थी।

विचारण न्यायालय के समक्ष समझौतों की वैधता और वास्तविकता पर कोई विवाद नहीं हुआ। विचारण न्यायालय ने यह कहते हुए वाद में डिक्री पारित की कि प्रत्यर्थी कंपनी अनुबंध के अपने हिस्से को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार और इच्छुक थी;

अपीलकर्ताओं द्वारा किसी भी समय समझौते को रद्द नहीं किया गया था; विनिर्दिष्ट पालन के लिए वाद परिसीमा अवधि के भीतर दायर किया गया था। चूँकि, प्रत्यर्थी-कंपनी 2.5.1974 से मुकदमे की संपत्ति पर कब्ज़ा कर रही थी, विनिर्दिष्ट पालन देने में न्याय, साम्या उसके पक्ष में है, इससे भी अधिक, जब प्रतिफल राशि का बड़ा हिस्सा कंपनी द्वारा पहले ही भुगतान किया जा चुका था। विचारण न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर अपीलों को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था।

इसलिए वर्तमान अपील प्रस्तुत हुई।

न्यायालय ने अपीलों का निस्तारण करते हुए माना:

1.1 उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने आदेश 41 नियम 1 सि.प्र.सं. 1908 के तहत शक्ति के कथित प्रयोग में अपीलों को खारिज कर दिया। हालाँकि, इस फैसले को

अपीलों को सीधे तौर पर खारिज करने वाला नहीं कहा जा सकता है, फिर भी प्रथम अपीलों के निपटान के तरीके में बहुत कुछ बाकी है।

मुकदमा विनिर्दिष्ट पालन के लिए था और विचारण न्यायालय ने प्रतिकूल कब्जे के बारे में निष्कर्ष दर्ज किए। ऐसा होने पर, विचारणीय मुद्दे शामिल हैं। जब विचारणीय बिंदु शामिल हों, तो अपीलों को सरसरी तौर पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए या इस तरीके से निपटाया नहीं जाना चाहिए। (पैरा - 6)

1.2 उच्च न्यायालय के फैसले को पढ़ने से पता चलता है कि उठाए गए विभिन्न बिंदुओं का विश्लेषण करने के लिए उसके द्वारा कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया था। (पैरा-7)

राजेश्वरी बनाम पूरन इंदौरिया (2005) 7 एससीसी 60 - का आश्रय लिया।

1.3 उच्च न्यायालय ने विनिर्दिष्ट पालन के लिए वाद में प्रतिकूल कब्जे के संबंध में एक निष्कर्ष दिया है। उच्च न्यायालय न्यायिक विवेक का प्रयोग करने में असमर्थ रहा। जिस तरीके से अपीलें खारिज की गईं, वह उचित नहीं कहा जा सकता। इसलिए, मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए उच्च न्यायालय को भेजा जाता है। (पैरा-8,9)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2004 की सिविल अपील संख्या 6329-6330

बेंगलुरु स्थित कर्नाटक उच्च न्यायालय के आर.एफ.ए. क्रमांक 608/2002 सी डब्ल्यू आर.एफ.ए. क्रमांक 609/2002 में दिनांक 4.6.2003 के निर्णय और अंतिम आदेश से।

अपीलकर्ताओं की ओर - के. परासरन, एस.के.कुलकर्णी, एम. गिरीश कुमार और विजय कुमार।

प्रत्यर्थी की ओर से - बी.दत्ता, ए.एस.जी. बी.के. सतीजा और बनमाली शुक्ला।

डॉ. अरिजीत पसायत, जे. द्वारा न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

1. इन अपीलों में कर्नाटक उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में 'सि. प्र. सं.') की धारा 96 के तहत दायर प्रथम अपील को खारिज कर दिया गया था। विनिर्दिष्ट पालन के लिए वाद को डिक्री करते हुए, XXXI अतिरिक्त सिटी सिविल जज, बैंगलोर की पत्रावली पर मूल वाद संख्या 285/1984 और मूल वाद संख्या 286/1984 में पारित निर्णय और डिक्री के विरुद्ध प्रथम अपील दायर की गई थी।

2. पृष्ठभूमि तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं:

प्रत्यर्थी द्वारा दो मुकदमे दायर किए गए, जिन्हें समेकित कर दिया गया। वादी के रूप में प्रत्यर्थी ने कुछ संपत्तियों के संबंध में विनिर्दिष्ट पालन की मांग की, जिन्हें कथित तौर पर अपीलकर्ता श्रीमती बी. सरोजा देवी और उनके पति श्री बी.के. हर्ष.द्वारा अनुबंध के तहत बेचने पर सहमति व्यक्त की गई थी। चूंकि दोनों अनुबंधों प्रदर्श पी-1 और पी-2

की वैधता और वास्तविकता विवादित नहीं थी, विचारण न्यायालय का विचार था कि विचार के लिए एकमात्र प्रश्न यह उठता है कि क्या प्रत्यर्थी विनिर्दिष्ट पालन की राहत का हकदार था। विचारण न्यायालय ने माना कि प्रत्यर्थी कंपनी अनुबंध के अपने हिस्से को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार और इच्छुक थी। यह भी पाया गया कि दोनों अनुबंधों को किसी भी समय अपीलकर्ताओं द्वारा रद्द नहीं किया गया था।

इसके अलावा, यह माना गया कि विनिर्दिष्ट पालन के लिए मुकदमा परिसीमा अवधि के भीतर दायर किया गया था। विचारण न्यायालय ने आगे कहा कि प्रत्यर्थी कंपनी 2.5.1974 से मुकदमे की संपत्ति पर कब्जे में है, इसलिए विनिर्दिष्ट पालन देने में न्यायसम्य उसके पक्ष में है और इससे भी अधिक, जब अनुबंध की प्रतिफल राशि का बड़ा हिस्सा कंपनी द्वारा पहले ही भुगतान किया जा चुका है। अत: इन दोनों वादों का निर्णय सुनाया गया। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उच्च न्यायालय ने प्रथम अपील को खारिज कर दिया।

3. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि निर्णय और डिक्री कई पृष्ठों तक चलती है, लेकिन इसका बड़ा हिस्सा विचारण न्यायालय के निर्णय के हिस्से के कथन और पुनरुत्पादन से बना है।

4. यह प्रस्तुत किया गया है कि यह प्रथम अपीलों के निपटान का उचित तरीका नहीं था। यह भी प्रस्तुत किया गया कि कुछ निष्कर्ष कानूनी रूप से असमर्थनीय थे। यह प्रस्तुत किया गया था कि जब वाद विनिर्दिष्ट पालन के लिए होता है, तो ऐसे वाद की विशेष विशेषताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए, जो कि नहीं किया गया है।

5. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने तथ्यात्मक और कानूनी स्थिति का विस्तार से उल्लेख किया था और इसलिए, निर्णय और डिक्री में हस्तक्षेप की आवश्यकता के लिए कोई कमी नहीं है।

6. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि निर्णय के पृष्ठ 4 से 18 (पेपर बुक में) विचारण न्यायालय के निर्णय के उद्धरण हैं। प्रमुख विवाद्यकों का संक्षेप में उल्लेख करने के बाद यह उद्धरण दिया गया। पेज 21 तक की दलीलें नोट कर ली गईं। विद्वान एकल न्यायाधीश ने आदेश 41 नियम 1 सि.प्र.सं. के तहत शक्ति के कथित प्रयोग में अपीलों को खारिज कर दिया। हालांकि सख्ती से कहा जाए तो निर्णय को अपीलों को सीधे तौर पर खारिज करने वाला नहीं कहा जा सकता है, फिर भी प्रथम अपीलों के निपटान के तरीके में बहुत कुछ बाकी है।

जब विचारणीय विवाद्यक शामिल हों, तो अपीलों को सरसरी तौर पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए या इस तरीके से निपटाया नहीं जाना चाहिए। वाद विनिर्दिष्ट पालन के लिए था और विचारण न्यायालय ने प्रतिकूल कब्जे के बारे में निष्कर्ष दर्ज किए।

अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील के अनुसार, ऐसा होने पर, विचारणीय विवाद्यक शामिल हैं। यह बताया गया कि अपीलकर्ताओं का तर्क, तत्परता की कमी, कथित विलंब, सीमित नवाचार से संबंधित था।

7. उच्च न्यायालय के निर्णय को पढ़ने से पता चलता है कि उठाए गए विभिन्न बिंदुओं का विश्लेषण करने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया था। यह प्रस्तुत किया गया कि अनुबंध को समाप्त करने का नोटिस दिया गया था। यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि वादी अनुबंध के अपने हिस्से को पूरा करने के लिए कभी भी तैयार और इच्छुक नहीं थे।

8. इस न्यायालय द्वारा कई मामलों में अनुबंध के विनिर्दिष्ट पालन के लिए वाद की प्रकृति पर प्रकाश डाला गया है। राजेश्वरी बनाम पूरन इंदौरिया (2005 (7) एससीसी 60) में, अन्य बातों के साथ-साथ यह माना गया :

> "5. आम तौर पर, अचल संपत्ति की बिक्री के लिए एक अनुबंध के विनिर्दिष्ट पालन के लिए वाद में यह सवाल शामिल होता है कि क्या वादी विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 16 के संदर्भ में अनुबंध के अपने हिस्से को पूरा करने के लिए तैयार और इच्छुक था, क्या यह विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, की धारा 20 के संदर्भ में विनिर्दिष्ट पालन को डिक्री करने के लिए न्यायालय द्वारा विवेक के प्रयोग का एक मामला था और क्या अनुबंध के विनिर्दिष्ट पालन को लागू करने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में वादी की ओर से कोई कमी थी।
>
> कुछ मामलों में, बिक्री के लिए अनुबंध की शर्तों पर परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 54 के संदर्भ में परिसीमा का प्रश्न भी उठ सकता है। कुछ मामलों में अन्य प्रश्न भी उठ सकते हैं, जैसे अनुबंध की

वास्तविकता, विनिर्दिष्ट पालन के अधिकार का परित्याग, नवीनता इत्यादि। इसमें कोई संदेह नहीं है, पहले बताए गए तीन प्राथमिक पहलुओं पर कोई निष्कर्ष आसपास की परिस्थितियों के आलोक में मामले में दलीलों और सबूतों के विवेचन पर निर्भर करेगा।

6. अचल संपत्ति की बिक्री के लिए एक अनुबंध के विनिर्दिष्ट पालन का अधिकार, जब दायर किया जाता है, तो पार्टियों के बीच पर्याप्त महत्व के प्रश्न उठते हैं कि क्या वादी ने विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 16 की आवश्यकताओं को पूरा किया है, क्या यह एक मामला है जिसमें अनुबंध का विनिर्दिष्ट पालन धारा 10 के संदर्भ में लागू करने योग्य है, अधिनियम की धारा 20 के संदर्भ में विनिर्दिष्ट पालन को डिक्री करने का विवेक न्यायालय द्वारा प्रयोग किया जाना चाहिए और कुछ मामलों में, क्या मुकदमा परिसीमा से वर्जित था और यदि नहीं, तो क्या वादी लापरवाही या विलंब का दोषी है जो उसे विशिष्ट निष्पादन के लिए किसी डिक्री के अधिकार से वंचित करता हो।

ये प्रश्न, कुल मिलाकर, सामान्य महत्व के कानून के प्रश्न नहीं हो सकते हैं। लेकिन उन्हें मामले में सबूतों के विवेचन के आधार पर तथ्य के शुद्ध प्रश्न भी नहीं माना जा सकता है। ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम और परिसीमा अधिनियम (यदि परिसीमा का प्रश्न शामिल है) के प्रासंगिक प्रावधानों के संदर्भ में निर्णय लिया जाना है।

यद्यपि ऐसा हो सकता है कि विवेक के प्रयोग में दिए गए किसी आदेश में कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल न हो, लेकिन यह प्रश्न कि क्या कोई अदालत, कानून के अनुसार, विनिर्दिष्ट पालन का आदेश देने के लिए विवेक का प्रयोग कर सकती है, कानून का एक प्रश्न हो सकता है जो उस वाद में संबंधित पक्षों के अधिकारों को काफी हद तक प्रभावित करता है।"

8. उच्च न्यायालय ने विनिर्दिष्ट पालन के लिए वाद में प्रतिकूल कब्जे के संबंध में भी एक निष्कर्ष दिया है। उपरोक्त स्थिति के सन्दर्भ में, न्यायिक विवेक का प्रयोग प्रतीत नहीं हो रहा है। जिस तरीके से अपीलें खारिज की गईं, वह उचित नहीं कहा जा सकता।

9. उपरोक्त स्थिति होने के कारण, आक्षेपित निर्णय रद्द किये जाने योग्य है। मामले पर नये सिरे से विचार करने के लिए, मामला उच्च न्यायालय को भेजा गया है। तदनुसार अपीलों का निपटारा किया जाता है।

खर्चे के रूप में कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

अपीलें निस्तारित

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी जगदीश जानी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।